भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1268
दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भेषज उत्पादों का निर्यात

1268. श्री चंद्र शेखर साहूः
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री राहुल रमेश शेवालेः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का भेषज उद्योग वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय भेषज उद्योग विशेषकर ओडिशा के उद्योगों का वर्तमान आकार कितना है;
(ग) क्या देश भारतीय और वैश्विक बाजारों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती दवाओं के विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है;
(घ) यदि हां, तो विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक भेषज उद्योगों द्वारा निर्यात की गई दवाओं और उपकरणों सहित तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) विगत नौ वर्षों के दौरान भेषज उत्पादों के निर्यात में हुई वृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा भेषज उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क): भारतीय औषध उद्योग ने वहनीय दवाओं तक पहुंच प्रदान करने और कई देशों के लिए स्वास्थ्य देखभाल व्यय को बचाने के मामले में विश्व स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय औषध उद्योग, जिसे "दुनिया की फार्मेसी" के रूप में भी जाना जाता है, भारत और विश्व स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय औषध उद्योग प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के विनिर्माण में अग्रणी बन गया है और विश्व स्तर पर वहनीय दवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2022-2023 के लिए

औषध का निर्यात 1,94,254 करोड़ रुपये रहा। उद्योग के अनुमान के अनुसार, लगभग 200 देशों/क्षेत्रों में निर्यात की मात्रा के हिसाब से भारत दवाओं और औषध के उत्पादन में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। भारतीय औषध उद्योग टीकों की वैश्विक मांग का 62 प्रतिशत आपूर्ति करता है और डीपीटी, बीसीजी और खसरे के टीकों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। डब्ल्यूएचओ के 70% टीके (आवश्यक टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार) भारत से प्राप्त होते हैं।

(ख): भारतीय औषध उद्योग मूल्य के मामले में दुनिया का 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में औषध उद्योग का मूल्य वर्तमान में □50 बिलियन (वर्ष 2021-22) है। ओडिशा में औषध उद्योग का आकार उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ): जी हां, भारत भारतीय और वैश्विक बाजारों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी दवाओं के विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों को निर्यात किए गए औषध उत्पादों और उपकरणों का विवरण इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (नवंबर, 2023 तक)**
औषधि फार्मूलेशन, जैविक	141634.12	156401.43	115837.78
चिकित्सा उपकरण	20427.26	27270.41	20373.41

(ङ): पिछले नौ वर्षों के दौरान औषध उत्पादों के निर्यात में वृद्धि का विवरण इस प्रकार है: -

वित्तीय वर्ष	**मूल्य (रुपये करोड़ में)**	**विकास दर (%)**
2014-15	68,557.75	-
2015-16	82,760.25	20.7
2016-17	84,934.89	2.6
2017-18	83,213.97	-2.0
2018-19	1,00,681.60	21.0
2019-20	1,13,003.65	12.2
2020-21	1,41,207.04	25.0
2021-22	1,41,634.12	0.3
2022-23	1,56,401.43	10.4

(च): सरकार आयात पर देश की निर्भरता को कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। सरकार औषध उद्योग को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है ताकि क्षेत्र में अधिक निवेश और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के लिए उत्पाद विविधीकरण को सक्षम किया जा सके। औषध विभाग निम्नलिखित तीन योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(i) **भारत में महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई) और सक्रिय औषध सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना** (पीएलआई बीडी) - योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से 2029-30 तक 6,940 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ है। इस योजना में छह (6) वर्षों के लिए 41 चिह्नित किए गए उत्पादों की बिक्री पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 48 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 3,630 करोड़ रुपये का निवेश पहले ही किया जा चुका है। अब तक 27 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं और 41,881 मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है। सितंबर 2023 तक योजना के अंतर्गत पीएलआई बीडी आवेदकों द्वारा पंजीकृत कुल निर्यात लगभग 252.62 करोड़ रुपये है।

(ii) **औषध हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना** - योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये है और योजना का कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-21 से 2028-29 तक है। यह योजना तीन (3) उत्पाद श्रेणियों के तहत अनुमोदित उत्पादों की बिक्री पर 6 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें बायो-फार्मास्यूटिकल्स, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक ड्रग्स, सेल आधारित या जीन थेरेपी ड्रग्स, ऑफ़्फ़न ड्रग्स, फाइटो-फार्मास्यूटिकल्स, पेटेंट दवाओं या पेटेंट समाप्ति के करीब दवाएं, आदि शामिल हैं। सितंबर, 2023 तक योजना के पीएलआई फार्मा आवेदकों द्वारा पंजीकृत कुल निर्यात लगभग 73,025 करोड़ रुपये है।

(iii) बल्क औषधि पार्कों के संवर्धन हेतु योजना पार्क में स्थित बल्क औषधि इकाइयों को साझा बुनियादी ढांचा सुविधाओं (सीआईएफ) तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि बल्क दवाओं की विनिर्माण लागत को काफी कम किया जा सके। इस योजना का वित्तीय परिव्यय 3,000 करोड़ रुपये है और कार्यकाल वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-25 तक है। यह योजना बल्क औषधि पार्क स्थापित करने के लिए तीन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विभाग को 13 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद, आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों में बल्क औषधि पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

*****